ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 135-142
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

वर्तमान में अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

1. डॉ0 सुशीला
2. नम्रता सिंह

1. असिस्टेंट प्रोफेसर, 2. शोध अध्येता– समाजशास्त्र विभाग, कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातक महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0), भारत

Received- 13.11. 2021, Revised- 19.11. 2021, Accepted - 24.11.2021 E-mail: quinsingh1@gmail.com

सारांश: ***तालिबान एक उग्रवादी समूह है, इसने 1990 के दशक के आखिर में अफगानिस्तान पर शासन किया था। अफगानिस्तान में अब यह दोबारा बड़ी ताकत बनकर उभरा है, और देश पर काबू कर लिया है 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में हमले किए और उग्रवादी को सत्ता से बेदखल किया। लगभग दो दशकों के बाद तालिबान के वापसी इससे देश में एक बार फिर अस्थिरता और अशांति का खतरा उत्पन्न हो गई है।***

तालिबान ने शरिया कानन को लागू किया है। ऐसे ही कानून उसने 1996 से 2001 के बीच अपने शासन में लागू किये थे। सब तालिबान के क्रूर शासन में महिलाओं को लगातार मानवाधिकारों के उल्लंघन, रोजगार और शिक्षा से वंचित किया। महिलाओं में डर है कि उनकी अधिकार दुबारा छीन लिये जायेंगे। तालिबान के सत्ता से बेदखल होने के बाद अफगान महिलाओं ने कई अधिकारों को हासिल किये थे। इस अध्ययन में अफगानिस्तान में महिलाओं की वर्तमान स्थिति का पता चलता है और महिलाओं की तालिबान के दस्तक से पूर्व स्थिति क्या थी और तालिबान के दस्तक के दस्तक के बाद महिलाओं की स्थिति क्या है।

कुंजीभूत शब्द– अफगानिस्तान, तालिबान, शरीया कानून, महिला स्थिति, उग्रवादी समूह, शरिया कानून, तालिबान।

अफगानिस्तान में लगभग दो दशकों के गैरनिर्णयक संघर्ष के बाद जैसे–जैसे अमेरिकी सेना पीछे हट गयी, देश में एक बार फिर अस्थिरता और अशांति का खतरा उत्पन्न हो गया है अफगानिस्तान में तालिबान के साथ इस्लामी कट्टरपंथ की वापसी समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों विशेषकर महिलाओं की स्वतंत्रता और सुरक्षा को लेकर चिंताए उठने लगी है। यदि हम 20 वर्ष पश्चात् के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो तब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा था। तालिबान ने शासन (वर्ष 1996 से लेकर वर्ष 2001) के दौरान जनता (विशेषकर महिलाओं) को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया। तालिबान अफगानिस्तान में महिलाओं को बगैर किसी पुरुष को साथ लिये घर से बाहर निकलने की अनुमति नही थी, महिलाओं की शिक्षा पर पूरी तरह प्रतिबन्धित कर दिया गया, नौकरी पर रोक लगा दी, राजनीतिक में हिसा लेने और सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखने की अनुमति नहीं थी, महिलाओं को पुरुष डाक्टरों से इलाज की अनुमति नहीं थी।

लेकिन वर्ष 2001 में तालिबान के शासन के अंत के बाद वर्ष 2004 के संविधान में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति में सुधार के लिए उनके सभी अधिकारों को पुनः स्थापित किया गया। महिलाओं को बेसिक राइट मिलने लगे। साल 2000 में जहाँ एक भी लड़की स्कूल नही जाती थी, वहीं 2018 में ये आंकड़ा 83 प्रतिशत हो गया था। नवम्बर 2001 की अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 90 के दशक के शुरूआत में अफगानिस्तान में स्कूलों में पढ़ाने वाले कुल टीचर्स में 77 प्रतिशत महिलाएं थीं, सरकारी पदों पर 50 प्रतिशत महिलाएं काम करती थीं और काबुल में कुल डाक्टरों में 40 प्रतिशत तक महिलाएं थी।

लेकिन अब वर्तमान समय में 20 साल बाद तालिबान का अफगानिस्तान पर पुनः कब्जा हो गया है। तालिबान महिलाओं को काम करने और ज्यादा आजादी देने की बात कर रहा हो, लेकिन ग्राउंड पर स्थिति इसके विपरीत है। तालिबान ने कहा है कि वो अफगानिस्तान को शरिया कानून के मुताबिक चलाएगा। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, कई जगह महिलाओं को बिना किसी पुरुष के घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। कई जगह सार्वजनिक स्थानों पर भी महिलाओं की एंट्री बैन कर दी गई है। यानी, तालिबान के आते ही महिलाओं की सख्ती की शुरूआत हो चुकी हैं काबुल की सड़कों पर महिलाओं की प्रदर्शन की तस्वीरे भी सामने आई है। हिजाब पहने इन महिलाओं को तालिबानी शासन के आने के बाद खुद की आजादी छिन जाने का डर है।

उद्देश्य – (1) अफगानिस्तान में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का अध्ययन।

(2) प्रस्तुत शोध के अन्तर्गत तालिबान के दस्तक देने के पूर्व एवं पश्चात की स्थिति का विश्लेषण करना।

1. तालिबान के दस्तक देने से पूर्व अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति – तालिबान के दस्तक देने से पूर्व अफगानिस्तान में एक दौर ऐसा था जब महिलाओं को बराबर के हक मिले हुये थे उन्हें पुरुषों के समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार एवं स्वतंत्रता प्राप्त थे। ये वो समय था जब देश में महिलाएं अपने पसंद के कपड़े पहनकर आजादी से घूम सकती थी और पार्टी भी कर सकती थी। 1970 के दशक में अफगानिस्तान में महिलाओं को मिनी स्कर्ट समेत की वेस्टर्न

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

कपड़ों में देखा गया था।

सिर्फ 1970 में ही नहीं बल्कि देश में महिलाओं को 1960 के दशक से ही आजादी मिलनी शुरू हो गई थी तब वहाँ की सरकार ने महिलाओं के लिए समान अधिकार कायम किए थे कुछ महिलाएं तो न सिर्फ विदेशी कपड़े तक पहन सकती थी बल्कि कुछ के तो अकेले ट्रेवल करने, यूनिवर्सिटी जाने और यहां तक की घर से बाहर जाकर काम करने का भी अधिकार मिला हुआ था। हीदर बार जो कि ह्यूमन राइट्स वॉच के साथ एक सीनियर रिर्सचर है उन्होंने भी इस बात पर एक इंटरव्यू के दौरान मोहर लगाई। हालॉकि उनका कहना है कि सभी जगहों पर महिलाओं को आजादी मिली हो ऐसा नहीं है ये आजादी सिर्फ शहरी और एलीट क्लास की महिलाओं के पास थी गांवों में रहने वाली जनता उस समय भी पिछले ख्यालों वाली थीं 60 के दशक में एक बड़ी अफगान आबादी गांव में ही रहती थी। सरकार की तरह से चलाये गये सुधार कार्यक्रमों के बावजूद परिवारों में पर्दा प्रथा की परम्परा जारी थी, इसकी वजह से महिलाओं को सार्वजनिक तौर पर बुर्का पहनना पड़ता था, काबुल जैसे शहरों में उन्हें आजादी मिली हुई थी। हीदर बार के मुताबिक अलग–अलग लाइफस्टाइल के लोगों में रहने की क्षमता भी अलग–अलग थी।

साल 1960 में अफगान सरकार ने जहॉ नया संविधान बनाया और इसमें महिलाओं के अधिकार सुरक्षित किए। वहीं साल 1970 में कुछ पश्चिमी मान्यताओं को जगह मिलनी शुरू हुई थी साल 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगान सरकार को गिराया तो वहां से महिलाओं की स्थिति बिगड़नी शुरू हो गई, साल 1996 में तालिबान ने पहली बार देश पर शासन किया था तालिबान ने देश में सख्त शरिया लॉ लागू कर दिया मगर साल 2001 में जब अमेरिकी फौज दाखिल हुई तो एक बार फिर महिला अधिकारों में बदलाव देखने को मिला वर्ष 2004 के संविधान में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति में सुधार के लिए उनके सभी अधिकारों को पुनः स्थापित किया गया।

तालिबान के दस्तक से पूर्व अफगानिस्तान में महिलाओं के अलग–अलग क्षेत्रों में स्थिति–

1. तालिबान के दस्तक से पूर्व अफगानिस्तान में महिलाओं की सामाजिक स्थिति– तालिबान के दस्तक से पूर्व अफगानिस्तान में महिलाओं को पुरुषों के समान सामाजिक अधिकार मिले थे। महिलाओं को पुरुषों के समान कैरियर, शिक्षा, फैशन, रोजगार और कानून–व्यवस्था के अनेक अवसर उपलब्ध थे। "यू0के0 का एक एन0जी0ओ0 है एमनेस्टी इंटरनेशनल, दुनियाभर में ह्यूमन राइट्स से जुड़ा डेटा इकट्ठा करता है। इसकी रिर्पोट्स का दावा है कि 1923 में औरतों को अपनी पसंद से शादी करने की कानूनी अधिकार मिल गये थे।" पिछले दशक में अफगान महिलाओं ने फुटबाल और बास्केटबॉल सहित विभिन्न प्रकार के खेलों में भाग लिया है। 50 साल पहले अफगान महिलाएँ मेडिकल में अपना कैरियर बनाती थी, लड़के–लड़कियॉ मूवी थियएटर और यूनिवर्सिटी कैम्पस में आजादी से मिलते थे, कानून– व्यवस्था थी। 70 के दशक अफगानिस्तान एक फैशन हब था पुरानी तस्वीरों में अफगॉन महिलाएं और पुरुष यूरोप से किसी देश की तरह फैशनेबल लग रहे है पुरानी तस्वीरों में अफगानिस्तान के फैशन की झलक नजर आती है।

70 के दशक की महिलायें

2001 में अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद तालिबान सत्ता से हआ तो महिलाओं की स्थिति में सुधार आना शुरू हुआ। महिलाओं को सामान्य अधिकार मिलने लगे। वर्ष 2018 तक अफगानिस्तान में 3,135 स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का उनका संचालन शुरू किया। अफगान सरकार के अनुसार, इन स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से देश की 87 प्रतिशत आजादी के लिए अनेक घर से 2 घंटे की दूरी से अंदर चिकित्सा सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित की जा सकी। वर्ष 2003 में अफगानिस्तान के प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित लड़कियों की संख्या 10 प्रतिशत से भी कम थी, हालॉकि सरकार के प्रयासों के बाद वर्ष 2017 तक यह संख्या बढ़कर 33 प्रतिशत तक पहुँच गई। इसी प्रकार वर्ष 2003 में माध्यमिक शिक्षा केन्द्रों में महिलाओं का नामांकन

मात्र 6 प्रतिशत ही थी। जो वर्ष 2017 तक बढ़कर 39 प्रतिशत तक पहुँच गया। सरकार द्वारा वर्ष 2017 में स्कूली शिक्षा में 35 लाख लड़कियों और विश्वविद्यालयों में लगभग 1 लाख लड़कियों के नामांकन के साथ महिलाओं के लिए शिक्षा की पहुँच को बढ़ाने का प्रयास किया गया।

वर्ष 2009 में अफगानिस्तान में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा उन्मूलन कानून को अपनाया। 2015 में अफगानिस्तान ने अपना पहला मैराथन आयोजित किया, जो लोग पूरे मैराथन भाग चुके थे उनमें से एक महिला जैनेक थी, जो 25 साल की उम्र में थी जो इस तरह अपने देश के भीतर मैराथन में दौड़ने वाली पहली अफगान महिला बन गई।

2. तालिबान के दस्तक से पूर्व अफगानिस्तान में महिलाओं की आर्थिक स्थिति – तालिबान के दस्तक से पूर्व अफगानिस्तान में महिलाओं को पुरुषों के समान आर्थिक समानता थी। महिलाओं को पुरुषों के समान कैरियर तथा रोजगार के अनेक अवसर मिले थे। पचास साल पहले महिलाएं मेडिकल में अपना कैरियर बनाती थी। यू0के0 का एक एन0जी0ओ0 एमनेस्टी इंटरनेशनल, दुनियाभर में ह्यूमन राइट्स से जुड़ा डेटा इकट्ठा करता है, इसकी रिपोर्टस का दावा है कि 1928 में अफगानी महिलाओं का एक ग्रुप तुर्की में स्कूल अटैंड करने गया था। 1940 से 1950 के बीच अफगान महिलाएँ नर्स, डॉक्टर और टीचर्स बनने लगी। साल 1959 से 1965 आते–आते अफगानी महिलाएँ सिविल सर्विसेस में, स्पोर्टस में खुलकर हिस्सा लेने लगी। 1965 में दो महिला सीनेटर चुनी गई थी और 1966 से 71 के बीच अफगानी अदालतों में 14 महिला जज पहुँच गई थी। एक रिपोर्ट का दावा है कि 60 के दशक में 8 प्रतिशत अफगान महिलाएं बाहर जाकर नौकरी करने लगी थी, खुद पैसे कमाने लगी थी।

1965 के बाद अफगानिस्तान में ऑफिस जाती महिलायें

2001 में अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद तालिबान सत्ता से हटा तो महिलाओं की स्थिति में सुधार आना शुरू हुआ। महिलाओं को वो अधिकार मिलने लगे जो उन्हें दशकों पहले मिले थे उन्हें काम करने का अवसर मिला, खुद पैसे कमाने का अवसर मिला। महिलायें हर क्षेत्र में काम कर रही थी महिलाये फैशन फोटोग्राफर, इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी चलाती है, मीडिया में एंकर है, नर्स है, डॉक्टर है आदि क्षेत्रों में काम करने की अधिकार और स्वतंत्रता मिली थी। अमानुल्लाह खान की पत्नी क्वीन सोराया का एक बयान 'कैनेडियन वुमन फॉर वुमन इन अफगानिस्तान' नाम की रिपोर्ट में दर्ज है "ये मत सोचिए कि सिर्फ मर्द देश की सेवा करे। इस्लाम के शुरूआती दिनों में औरतों ने बढ़–चढ़ कर समाज की सेवा की है। हमे भी अपने देश के विकास में हिस्सा लेना है लेकिन ये बिना पढ़ाई– लिखाई के नही होगा। इसलिए घरों से निकलिए! ज्ञान हासिल कीजिए।"

3. तालिबान के दस्तक देने से पूर्व अफगानिस्तान में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति– 1960 के दशक में अफगानिस्तान में महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में अधिकार एवं स्वतंत्रता मिली हुई थी। 1960 के दशक के नये संविधान में महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी के साथ–साथ जीवन के अन्य क्षेत्रों में समान अधिकार दिये गये थे। 1964 में आए तीसरे संविधान में महिलाओं को राजनीति में आने की अनुमति मिली और वोट का अधिकार भी मिला। 1965 में दो महिला सीरेटर चुनी गई। यू0के0 का एक एन0जी0ओ0 एमनेस्टी इंटरनेशनल, दुनियाभर में ह्यूमन राइट्स से जुड़ा डेटा इकट्ठा करता है इसकी रिपोर्ट्स का दावा हे कि 1919 में अफगान महिलाओं को वोट देने का अधिकार था।

2001 में अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद तालिबान सत्ता से हटा तो, महिलाओं की स्थिति में सुधार आना शुरू हुआ। महिलाओं को राजनीति में बेसिक राइट मिलने लगे। साल 2004 में अफगानिस्तान का नया संविधान बना था वहां महिलाओं को समान अधिकार का प्रावधान रखा गया, महिलाओं को कई क्षेत्रों में आरक्षण दिया संसद में 27 प्रतिशत आरक्षण था। 2017 में अफगान संसद में 28 फीसदी महिलाएं थी। वहीं 2018 में हुए आम चुनावों में 249 में से 69 सीटों पर महिलाओं की जीत मिली थी। यानी कुल सदस्यों में 27 प्रतिशत महिलाएं थी ये आंकड़ा पाकिस्तान और चीन से भी ज्यादा था। इन 20 साल में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर राजनीति में अपनी पहचान बनाई थी।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

अफगान राष्ट्रीय पुलिस

अफगान संसद के सदस्यों के रूप में कई महिलाएं शुक्रिया बराकजई, फौजिया गेलानी, निलोफर इब्राहिनी, फैजिया कोआमी, मलालाई जॉय और कई अन्य महिलाएँ शामिल है। कई महिलाओं ने सुहेला से दिक्की सिमा समर, हुसैन बनू गजानफर और सुराया दलील सहित मंत्रियों के पदों पर भी पदभार संभाला। अफगानिस्तान में हबीबा सरबी पहली महिला गर्वनर बन गई। उन्होंने महिला मामलों के मंत्री के रूप में भी कार्य कियां आजरा जाफरी दयांडी प्रांत की राजधानी नीति की पहली महापौर बन गई। वही अफगानिस्तान की पहली मेयर जरीफा गफारी है।

2. तालिबान के दस्तक के बाद अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति– पहली बार तालिबान अफगानिस्तान पर 1996 से 2001 तक शासन किया था इस दौरान महिलाओं की स्थिति बेहद चिंताजनक थी उन्हें पुरुषों के समान जीवन के हर क्षेत्रों में (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक) अधिकार तथा स्वतंत्रता नहीं प्राप्त थी। कब्जा लेते ही तालिबान में अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू किया। शरिया कानून के तहत महिलाओं पर कई नियम लागू किये जो इस प्रकार है–

– बिना मर्द को साथ लिए कोई महिला घर से बाहर नही निकल सकती।

– घर से बाहर निकलते वक्त पर्दा न करना अपराध है। बाहर रहने पर ऐसा कोई कपड़ा नही पहन सकती जिससे शरीर का कोई अंग दिखाई दे।

– किसी मर्द डॉक्टर से चेकअप नहीं करा सकती।

– जब कोई महिला काम ही नहीं कर सकती तो महिला डॉक्टर बनेगी नही, और पुरुषों से महिलाएँ चेकअप नहीं करा सकती, ऐसे में महिलाओं को डॉक्टरी सुविधा ही नहीं मिली।

– कोई लड़की पढ़ाई नही कर सकती।

– किसी खेल में हिस्सा लेना तो दूर, स्टेडियम जाकर कोई खेल देख भी नहीं सकती। अगर कोई महिला बिना मर्द को साथ लिए घर से बाहर आ गई तो तालिबान समर्थक या तालिबानी सेना के लोग ऐसी महिलाओं को सरेआम पीटने लगते थे।

– संगीत नही सुन सकती, सिनेमा नही देख सकती, सारे सिनेमाहॉल तोड़ दिए गए थे।

– अपने घर के दरवाजे–खिड़कियॉ बंद रखनी होगी, ताकि बाहर से कोई किसी महिला को न देख ले।

– अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकती। जब 2020 में काबुल के गाजी स्टेडियम क्रिकेट लीग शुरू हुई तो यह सूब चर्चा हुई थी। ये वही स्टेडियम है, जिसमें 1999 में एक महिला पर अश्लीलता के आरोप लगाकर उसकी सरेआम हत्या कर दी गई थी।

ह्यूमन राइट्स की एक रिपोर्ट कहती है कि तब 1996 से लेकर 1998 के बीच 2 सालों के भीतर 100 गर्ल्स स्कूल बंद कराये गए थे। अगर कोई शरिया कानून की बातों को न मानने की जुर्रत करता था तो उसे कोड़े मारे जाते थे, सरेआम चौराहे पर लाकर पत्थर मार–मार कर जान ले ली जाती थी भले वो नाबालिक हो।

एक बार फिर तालिबानी सेना ने काबुल (15 अगस्त 2021) को कब्जा कर लिया। अगले कुछ दिनों में तालिबान ने पूरे अफगान पर अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया। तालिबान के देश में वापस लौटने से सबसे ज्यादा बुरा हाल महिलाओं का है। महिलाओं को डर है कि उनके अधिकार दुबारा छीन लिये जायेंगे। उन पर वही प्रतिबंध लगा लिये जायेंगे जो 20 साल पहले उन पर लगे थें तालिबान के शासन के लौटने के साथ ही महिलाओं की अपने भविष्य को लेकर सारी उम्मीद टूट गई है। पिछले 2 दशकों में पत्रकारों और एनजीओ के लिए काम करने वाली महिलाओं ने जो कुछ हासिल किया है, वह सब व्यर्थ जोयगा और तालिबान उनके काम पर प्रतिबंध लगा देगा। फुलर प्रोजेक्ट की एडिटर इन–चीफ खुशबू शाह ने एक ट्विटर थ्रेड में दुनिया के साथ साझा किया कि अफगानिस्तान में महिलाएं किस दौर से गुजर रही है। हाल के शासन के दौरान, तालिबान ने महिलाओं को घर से बाहर काम करने या स्कूल जाने से रोक लगा दिया था। महिलाओं को बुर्का पहनना अनिवार्य

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

था और जब भी वे बाहर जाती थी उन्हें एक पुरुष रिश्तेदार के साथ जाना पड़ता था।

काबुल की सड़कों पर महिलायें अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रही है। हिजाब पहने इन महिलाओं को तालिबानी शासन के आने के बाद खुद की आजादी छीन जाने का डर है। आन्दोलन के समय महिलाये हिजाब पहने दिखी। इससे तालिबान शासन के खौफ का अन्दाजा लगाया जा सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद यहां भगदड़ मच चुकी है और देश के अधिकतर लोग यहां से पलायन करके किसी दूसरे देश में बसना चाहते है। अफगानिस्तान से भागने की कोशिश में कई लोग अनी जान भी गवां चुके है।

बड़ी संख्या में लोग अफगानिस्तान से पलायन कर रहे है उनमें महिलाएं भी है। कुछ महिलायें ऐसी है जो अफगानिस्तान से निकल गई है वहीं कुछ महिलायें ऐसी है जो देश छोड़ने में असमर्थ है। काबुल की महिला रिपोर्टर जो देश छोड़ने में असमर्थ है ने कहा "अपने जीवन भर सहा है और अब आगे भी सहते ही रहेगें।" तालिबान के एक अधिकारी का टेलीविजन पर लाइव इंटरव्यू करने वाली और फिर अपने जान से डर से देश से भागने वाली पहली महिला अफगान पत्रकार बेहेश्ता अरगंध के कतर में एएएफपी को बताया कि अफगानिस्तान में महिलाएं "बहुत बुरी स्थिति है।"

अफगानिस्तान में मौजुदा हालात को समझने के लिए कुछ महिलाओं के कथन– अफगानिस्तान में चुनाव आयोग की पूर्व सदस्य जारमीना काकर ने बीबीसी को बताया, "इन दिनों मुझसे कोई पूछता है कि मैं कैसी हूँ तो इस सवाल पर मेरी आंखों में आसू आ जाते है और मैं कहती हूं कि ठीक हूं, लेकिन असल में हम ठीक नहीं है। हम ऐसे दुखी पंछियों की तरह हो गए है जिनकी आंखों के सामने घुंध छायी हुई है। और हमारे घरौंदा को उजाड़ दिया गया है। हम कुछ नहीं कर सकते, केवल देख सकते है और चीख सकते है।

अफगानिस्तान की फैशन फोटोग्राफर फातिमा कहती है कि अफगानी महिलाएं दुनिया की सबसे स्टाइलिश औरतों में मानी जाती है, पर तालिबान के लौटने से उन्हें फिर से बुर्के में लौटना पड़ेगा।

काबुल यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स कर रही आयशा कहती है "मेरे फाइनल सेमेस्टर पूरे होने में महज दो महीने बाकी रह गए लेकिन अब मैं शायद ही कभी ग्रेजुएट हो पाऊं। लोग सदमे में है हम समझ नही पा रहे है कि हम कैसा महसूस करें।"

तालिबान के दस्तक के बाद अफगानिस्तान में महिलाओं की अलग–अलग क्षेत्रों में स्थिति–

1. तालिबान के दस्तक के बाद अफगानिस्तान में महिलाओं की सामाजिक स्थिति – तालिबान के शासन (वर्ष 1996 से लेकर 2001 तक) के दौरान महिलाओं को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया। तालिबान के पहली दस्तक में महिलाओं को कोई अधिकार या स्वतंत्रता नहीं दी गयी। इस दौरान महिलाओं की सामाजिक स्थिति काफी चिन्ताजनक थी। महिलाओं के प्रति तालिबान के रूख की पहली झलक नवंबर 1996 को जारी एक आदेश में मिली, जिसने औरतों की ऊँची एड़ी की चप्पले और जूते पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। उनके मेकअप करने और फैशन वाले कपड़े पर रोक लगा दी गई। महिलाओं को संबोधित आदेश में कहा गया "तुम लोग अपने घर से बाहर नही निकलोगी, अगर तुमहारा घर से निकलना बहुत ही जरूरी हो जाए, तो तुम्हे इस्लामी शरिया कानून के अनुसार अपने आप को पूरी तरह ढक कर निकलना होगा। धार्मिक पुलिस के लोगों को सिर्फ इस बात पर पीटना शुरू कर दिया कि औरते ने बुर्का ढंग से नही पहना हुआ था। संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता ने अक्टूबर 1996 में एक वक्तव्य जारी कर कहा था कि तालिबान ने सत्ता संभालने के तीन महीनों के अंदर काबुल में 63 स्कूलों को बंद कर दिया था जिसकी वजह से 7800 महिला अध्यापकों की नौकरी चली गई थी। कार्ला पावर ने न्यूजवीक में छपे एक लेख में बताया। उन्होंने लिखा था, दर्जियों को हुक्म था कि वो महिलाओं के कपड़े सिलने के लिए उनकी नाप न ले बल्कि अपनी महिला ग्राहकों की नाप को अपने दिमाक में याद कर ले सारी फैशन पत्रिकाओं को नष्ट कर दिया गया, औरतों के नेल पेंट लगाने, दोस्त की तस्वीर खीचने, ताली बजाने, चाय पर किसी विदेशी को आमंत्रित करने पर सजा का प्रावधान कर दिया गया।

पहली तालिबान के दस्तक के बाद महिलायें

अफगानिस्तान में तालिबान के दुबारा दस्तक के बाद देश के लोगों में डर और घबराहअ का माहौल पैदा हो गया

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

है। तालिबान के देशों में वापस लैंटने से सबसे ज्यादा बुरा हाल महिलाओं का है। महिलाओं को डर है कि उनकी सामाजिक अधिकार दुबारा छीन लिये जायेंगे। हॉल के शासन के दौरान, तालिबान ने महिलाओं को घर से बाहर काम करने या स्कूल जाने से रोक दिया था। महिलाओं को बुर्का पहनना अनिवार्य था और जब भी वो बाहर जाती थी तो उन्हें एक पुरुष रिश्तेदार के साथ जाना पड़ता था। तालिबान ने 15 से 45 साल की अकेली महिलाओं और विधवाओं की सूची बनाकर देने को कहा है, ताकि तालिबानी लड़के उनसे शादी कर सके। तालिबान की वर्तमान गतिविधियों को देखते हुए लग रहा है कि महिलाओं का डर कहीं न कही सच है। वही अफगानिस्तान में तलाकशुदा महिलाओं का जीवन मुश्किलों और चुनौतियों से भरा है। रूढ़ीवादी समाज में तलाकशुदा महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं होती है। वही दूसरी ओर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर इन दिनों दिखाई जा रही है जिसमें एक ब्यूटी सैलून के मालिक को महिलाओं के चित्रित पोस्टरों पर पेटिंग करते हुए दिखाया गया। काबुल में मौजूद एक महिला पत्रकार कहती है, रातो रात महिलाओं के लिए पूरा शहर बदल गया है यहां तक कि सड़क पर चलना भी लगता है। जीवन रूक गया है।

अफगानिस्तान में महिलाओं के खेलों में भाग लेने पर रोक लगा दी गई है, तालिबान ने कहा कि अफगान महिलाएं क्रिकेट सहित खेलों में भाग नहीं ले सकती, क्योंकि खेलने के दौरान उनके शरीर को देखा जा सकता है। तालिबान के सांस्कृतिक कमीशन के डिप्टी हेड अहमदुल्ला वाशिक ने मीडिया से कहा कि खेल महिलाओं के लिए जरूरी नही है तालिबान द्वारा संचालित शिक्षा मंत्रालय ने सातवी से 12वीं कक्षा के लड़के को अपने पुरुष शिक्षकों के साथ से स्कूल आने को कहा लेकिन इन कक्षाओं में स्कूल आने वाली लड़कियों का कोई जिक्र नहीं किया गया।

2. तालिबान के दस्तक के बाद अफगानिस्तान में महिलाओं की आर्थिक स्थिति– 20 साल बाद अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान का शासन लौट आया है। चरमपंथी विद्रोही समूह से महिलाएं हमेशा से डरती रही है। अब तालिबान ने देश पर अपना कब्जा जमा लिया है तो महिलाओं को डर है कि ये उनके सबसे बुरे सपने के सच होने के जैसा होगा। 2001 से पहले जब अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन था, उस समय महिलाओं के लिए कानून काफी दमनकारी थे महिलओं को न पढ़ने की इजाजत थी न ही बाहर काम करने की। तालिबान के शासन के लौटने के साथ ही महिलाओं को अपने भविष्य को लेकर चिन्ता हो रही। उन्हें अपने आर्थिक निर्भरता तथा स्वतंत्रता खोने का डर है। नौकरी करने वाली महिलायें जो इतनी सालों में हासिल किया उस पर प्रतिबन्ध लग जायेगा।

नये तालिबान ने न्यूज चैनलों में महिला न्यूज रीडर और जर्नलिस्ट्स को घर बैठने को कह दिया गया। तालिबान लड़को ने दक्षिणी शहर कंधार में अजीजा बैंक में घुसे और वहां काम करने वाली 9 महिलाओं को वहां से बाहर जाने को कहा और वहां वे अब दुबारा नौकरी पर न जाएं। 43 साल की महिला नूर खतेश ने कहा कि काम पर वापस नही जाने देना अजीब है लेकिन अब यही सच्चाई है उन्होंने कहा कि नौकरी के दौरान उन्होंने कम्प्यूटर चलाना और अंग्रेजी बोलना सीखा लेकिन अब सब कुछ बेकार है। इसी तरह लड़के हेराल की एक बैंक में घुसे और दो महिला कैशियरों को चेतावनी दी कि वे अपना चेहरा ढक कर रखे, जिसके बाद उन्हें पुरुष साथी के साथ घर भेज दिया गया।

मीडिया रिर्पोटस के मुताबिक अलग–अलग क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं कहती है कि अब लोकतांत्रिक दुनिया से खुद को अलग–थलग महसूस कर रही है। जिसका वे कभी हिस्सा थी। वही कुछ महिलायें तालिबान सत्ता के आने के बाद देश से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। एक महिला पत्रकार बताती है कि हवाई अड्डे के रास्ते में बंदूक को नोक पर उन्हें लूट लिया गया। उनका पासपोर्ट और दस्तावेज ले लिए गए, लेकिन वह हवाई अड्डे पर पहुँचने में कामयाब हुई।

अफगानिस्तान की टीवी पत्रकार शबनम दावरान ने तालिबान के इरादों की कलाई खेाल दी है। शबनम दावरान ने दुनिया को बता दिया है कि तालिबान ने उन्हें काम करने से रोक दिया। शबनम ने बताया कि तालिबान ने उनसे कहा तुम एक महिला हो अपने घर जाओ। तुम यहॉं काम नहीं कर सकती हो।

3. तालिबान के दस्तक के बाद अफगानिस्तान में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति– पहली बार तालिबान जब अफगानिस्तान पर शासन किया था। इस दौरान महिलाओं की स्थिति बेहद चिन्ताजनक थी। उन्हें पुरुषों के समान राजनीतिक क्षेत्र में अधिकार तथा स्वतंत्रता नहीं प्राप्त थी। एक बार फिर तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से ही डर बना हुआ है कि अफगानिस्तान तालिबान में एक बार फिर से महिलाओं के अधिकारों का दमन कर दिया जायेगा। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के गठन के बाद वहॉं पर महिलाओं की सरकार में भागीदारी को लेकर प्रदर्शन हो रहे है। हालांकि महिलाओं द्वारा किया गया प्रदर्शन बेहद छोटा था, लेकिन तालिबान उसमें भी हिल गया। तालिबान के लड़कों द्वारा महिलाओं को पीटा गया वहॉं मौजूद पत्रकारों को भी मारा गया। अब सरकार गठन के तुरन्त बाद तालिबान ने ऐलान कर दिया है बिना सरकार के परामर्शन के किसी तरह के प्रदर्शन की इजाजत नही दी जायेगी।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

अफगानिस्तान में अपने हक के लिए प्रदर्शन करती महिलायें

स्थानीय मीडिया टोल न्यूज ने तालिबान के प्रवक्ता के हवाले से ट्वीट कर कहा, एक महिला मंत्री नहीं हो सकती यह ऐसा है जैसे आप उनके गले में डालते है जिसे वह सम्भाल नही सकती, एक महिला के लिये कैबिनेट में होना जरूरी नही है उन्हें बच्चे पैदा करना चाहिए, महिला प्रदर्शनकारी पूरे अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व नही कर सकती है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला पत्रकार तालिबानी लड़कों से पूँछ रही है कि क्या अफगानिस्तान में उनका राज्य आने के बाद क्या महिलाओं के अधिकारों का सम्मान किया जायेगा। इस पर लड़के कहते है कि इस्लामिक कानून यानी शरिया के मुताबिक, महिलाओं को सारे अधिकार मिलेंगे। इसके बाद महिला पत्रकार पूँछती है कि क्या अफगानी नागरिकों को किसी महिला को वोट देकर सत्ता में ला सकेंगे। तालिबान लड़के महिला पत्रकार के इस सवाल पर जवाब दिए बिना ठहाके लगाने लगते है इसके बाद ही पत्रकार से कैमरा बन्द करने के लिये कहा जाता है वीडियो में एक लड़के की आवाज सुनी जा सकती है जो अंग्रेजी में कहता है कि इस सवाल पर मुझे हँसी आ गयी है।

तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद कहा कि वह एक उदारवादी सरकार का गठन करेगा। इसने महिला अधिकारों समेत तमाम जरूरी अधिकारों को जगह दी जायेगी, जो तालिबान के पहले शासनकाल में मौजूद नहीं रहे थे। तालिबान ने अपनी अंतरिम सरकार बना ली, लेकिन यह जिस रूप में सामने आयी, उससे दुनिया को उस पर भरोसा होना संभव नही। क्योंकि सरकार समावेशी नही है जो उन्होंने पहले कहा था। इससे तालिबान की कथनी और करनी में फर्क दिख रहा हैं तालिबान 2.0 तालिबान 1.0 से बिल्कुल अलग नही है। इस 33 सदस्यीय अंतरिम सरकार ने किसी भी महिला को मंत्री के तौर पर शामिल नही किया गया है। इसके बाद से इस आशंका है कि इस तालिबान राज्य में अफगान महिलाओं की स्थिति और बदत्तर होने वाली है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार (UNHRC)– की प्रमुख मिशेल– बारवेलट– का कहना है कि तालिबान का महिलाओं और लड़कियों के साथ बर्ताव खतरे की एक मूलभूत लाल लकीर है।

हाल में अफगानिस्तान के नये तालिबान शासकों ने कभी महिला मामलों का मंत्रालय रहे एक भवन से शनिवार को विश्व बैंक के कार्यक्रम के कर्मचारी को जबरन बाहर कर "सदाचार प्रचार एवं अवगुण रोकथाम मंत्रालय" स्थापित किया है। काबुल पर कब्जा सरकार में आने के महज एक महीने बाद तालिबान द्वारा महिलाओं के अधिकारों पर पाबंदी लगाने वाला यह एक नया कदम है।

सुझाव– अफगानिस्तान के संदर्भ में यदि देखते है तो महिलाओं की स्थिति अत्यन्त सोचनीय है उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए निम्न सुझाव दिये जा सकते है–

– संयुक्त राष्ट्र को अफगानिस्तान में महिलाओं के खिलाफ और अत्याचारों को रोकने के लिये अब निर्णायक कार्यवाही करनी चाहिये।

– संयुक्त राष्ट्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान के संविधान, राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून में निहित महिलाओं के अधिकारों का सम्मान किया जाय।

– अफगान महिलाओं की सार्थक भागीदारी के बात वार्ता जारी रखने पर जोर दिया जाये।

– तालिबान के खिलाफ प्रतिबंध घटाना महिलाओं के अधिकारों को बनाये रखने की उनकी प्रतिबद्धता पर सर्तक होना चाहिए।

– यूरोपीय संघ और अमेरिका, महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा और रोजगार तक उनकी पहुँच पर सशर्त सहायता देनी चाहिए।

निष्कर्ष– 1996–2001 के दौरान तब तालिबान ने बेहद कट्टर शासन किया था और शरिया नियमों को सख्ती के साथ लागू किया था तब महिलाओं के काम करने तथा स्कूल और कॉलेज आदि पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। वही अब तालिबान ने महिलाओं को शर्तों के साथ सरकारी नौकरी, निजी सेक्टर एवं अन्य रोजगारों में काम करने की अनुमति दी है।

तालिबान का कहना है कि महिलायें कामकाज के लिये निकल सकती है, लेकिन उन्हें शरियत के नियमों का पूरा पालन करना होगा। तालिबान ने यह दावा करने के बावजूद उन्होंने महिलाओं के अधिकारों पर अपना रूख बदल लिया है। अतीत में महिलाओं पर किये गये अत्याचारों को देखते हुये इस पर भरोसा करना मुश्किल मालूम पड़ता है। तालिबान के सरकार के गठन और हालिया कार्यों और गतिविधियों हजारों महिलाओं के यौन दासता की ओर ठकेलने के यह ताजा इरादे उसके दावों के खिलाफ नजर आते है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. दृष्टि The Vision (17 Oct 2020) www.drishtiias.com
2. NBT नव भारत टाइम्स (14 Aug 2021) https://novbharattimes.indiatimei.com
3. TV9 भारत वर्ष (18 Aug 2021) https://www.tvihindi.com
4. नई दुनिया (18 Aug 2021) https://www.naidunia.com
5. अमर उजाला (20 Aug 2021) https://www.amarujala.com
6. BBC New (24 Aug 2021) https://www.bbc.com
7. BBC New (28 Aug 2021) https://www.bbc.com
8. हिन्दुस्तान (03 Sept 2021) https://www.livehindustan.com
9. हिन्दुस्तान (08 Sept 2021) https://www.livehindustan.com
10. आजतक (09 Sept 2021) https://www.aajtak.in
11. TV9 भारतवर्ष (09 Sept 2021) https://www.tvihindi.com
12. दैनिक भास्कर www.baskar.com
13. TV9 भारतवर्ष (18 Sept 2021) https://wwwtvIhindi.com
14- w.livehindustan.com

*****